

KGG-PSV/1A/11.00

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members are informed that as announced yesterday, the time for giving amendments to the Constitution (One Hundred and Twenty-first Amendment) Bill, 2014, and the National Judicial Appointments Commission Bill, 2014, is up to 11.30 a.m. Thereafter, no amendments will be accepted. Members are requested to cooperate.

Now, Question No.521. ..(Interruptions)..

श्री नरेश अग्रवाल: सर, आज क्वेश्चन ऑवर नहीं। ...(व्यवधान)... आज क्वेश्चन ऑवर नहीं, सर। ...(व्यवधान)... आज क्वेश्चन ऑवर मत कीजिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Parliamentary Affairs Minister has written to you. ...(Interruptions)...

श्री सभापति: नहीं, क्वेश्चन ऑवर में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है।
...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले लीजिए। आज क्वेश्चन ऑवर नहीं लीजिए। ...(व्यवधान)... आज क्वेश्चन ऑवर को डिस्पेंस कर दीजिए और कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: आज क्वेश्चन ऑवर नहीं लीजिए। ...(व्यवधान)... आज इसे सस्पेंड कीजिए। ...(व्यवधान)... यह प्रिसिडेंट नहीं माना जाएगा। ...(व्यवधान)... इसे प्रिसिडेंट मत बनाइए, लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जो शैड्यूल्ड बिजनेस है, उसको चलने दीजिए। ...(व्यवधान)... शरद जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... One minute, ...(Interruptions)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, पहले कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, पूरा हाउस यह चाहता है कि ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: One by one. ...(Interruptions)... One by one. ...(Interruptions)... शरद जी, बताइए।...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सभापति जी ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Parliamentary Affairs Minister has written to you with a request to suspend Question Hour to take up the Bill. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: We have sufficient time to be able to do both.
..(Interruptions)..

श्री नरेश अग्रवाल: सर, पूरा सदन चाहता है। ...(व्यवधान)... आप पूरे सदन से पूछ लीजिए। ...(व्यवधान)... रेग्युलेशन कर लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... शरद जी, आप बताइए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सभापति जी, ...(व्यवधान)... वे बैठें, तब तो मैं बोलूँ।
...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ..(Interruptions).. Please sit down. ..(Interruptions).. One minute, please.

श्री शरद यादव: सभापति जी, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और इसको एक घंटे में पूरा करना है और सरकार की भी इच्छा है कि एक बजे तक इसको पूरा करना है। ...(व्यवधान)... सर, यह बिल जो है, इससे देश के लोकतंत्र का जो इतना बड़ा खंभा है, उसके बारे में एक रास्ता निकालना है। तो इस पर सारे लोगों की बहस और राय आनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि अगर सरकार एग्री हो, तो जो क्वेश्चन ऑवर है, इसको ...(व्यवधान)... इसमें कोई हर्ज नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रकाश जी, आप क्या कहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सभापति जी, अगर सदन की इच्छा चर्चा करने की है और बिल सचमुच महत्वपूर्ण है, तो आज क्वेश्चन ऑवर को डिस्पेंस किया जा सकता है।...(व्यवधान)... यही तो हमारी भी इच्छा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please. ..(Interruptions).. आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर: यह पूरे सदन की इच्छा है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, प्लीज़। ...(व्यवधान)... Please sit down. ..(Interruptions).. Don't keep standing. That is not correct, please sit down. ..(Interruptions)..

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, मुझे इसके बारे में नहीं कहना है। लेकिन आज क्योंकि ज़ीरो ऑवर नहीं होने वाला है, इस वजह से मैंने यह मुद्दा उठाया है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ...(व्यवधान)... अगर आपको बोलना है, तो आप ज़ीरो ऑवर में अपना सवाल उठाइएगा। ...(व्यवधान)... वह इस वक्त नहीं उठाया जा सकता।...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, आज ज़ीरो ऑवर नहीं होने वाला है, ...(व्यवधान)... इसके लिए मैं यह मुद्दा अभी उठा रहा हूँ, सर। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: See, this is not Zero Hour.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, give me only two minutes, I don't want more time.

MR. CHAIRMAN: What do you want to say? Can you just mention the subject?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)... ज़ीरो ऑवर
...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: What is the subject?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, सवाल यह है कि कितने दिनों से पाकिस्तान रेंजर्स भारत की सीमा पर, एलओसी के अन्दर हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उसे आप ज़ीरो ऑवर में उठाइए या स्पेशल मेंशन दीजिए।
...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए, सर। ...(व्यवधान)... यह बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Okay, fine; thank you. ..(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I can't give Zero Hour time today. ..(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, वहाँ बीएसएफ के जवान मारे गए हैं। ...(व्यवधान)...
प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान)... आप स्पेशल मेंशन दीजिए।
...(व्यवधान)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No Zero Hour today, Sir.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अगले 15 अगस्त को ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, हम कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं और ये ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ..(Interruptions).. Please don't take the precious time. Please sit down. ..(Interruptions).. Please sit down. ..(Interruptions).. बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... This is not going on record. Why are you unnecessarily interrupting? Please sit down. ..(Interruptions).. Please sit down. ..(Interruptions)..

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: *

MR. CHAIRMAN: Please sit down. There is no Zero Hour today. ..(Interruptions).. You can't impose Zero Hour on us. I am sorry. ..(Interruptions).. आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... Please sit down. ..(Interruptions)..

(1बी/वीएनके पर आगे)

* Not recorded.

VNK-TDB/1B/11.05

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, यह कौन-सा तरीका है? ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: कांग्रेस यह जान-बूझकर कर रही है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(Interruptions)... Please sit down. ... (Interruptions)... I have not called you. ... (Interruptions)... Please let me work it out. Hon. Members, please sit down. ... (Interruptions)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have one point.

MR. CHAIRMAN: What is your point?

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the point is, we are ready to discuss the Bill. We want a detailed discussion on the Bill. But, as per the rule, Sir, a motion should be there to suspend the Question Hour. Then, I request the Government to move a motion for suspension of the Question Hour.

MR. CHAIRMAN: We are not talking of suspending the Question Hour. So, don't make a motion. ... (Interruptions)... Question No. 521. Let it be answered. ... (Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, अगर पूरा सदन सहमत है ...(व्यवधान).... सर, पूरे सदन पर चेयर की इच्छा थोपी नहीं जा सकती है। ...(व्यवधान)....

DR. V. MAITREYAN: Sir, we urge you to suspend the Question Hour.(Interruptions)... Sir, all political parties unanimously request you to suspend the Question Hour.(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, how long will it take? The hon. Minister should come out with a correct date when these two reports are going to be finalized?(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I have great respect for you, but... ..(Interruptions)... But you can't speak for all political parties.(Interruptions)... I am sorry. Please allow the Question Hour to proceed.(Interruptions)... One minute, please.(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: What are the contents of it so far? It is difficult for the administration of Andhra Pradesh and Telangana.(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: One minute. एक मिनट बैठ जाइए, the expressed anxiety about availability of time for the Constitution (Amendment) Bill and the associated Bill has been discussed threadbare. We have enough time. The time allotted will be taken for it. शरद जी का जो प्वाइंट था and we have enough time. We will have *sine die* in the afternoon,

as has been suggested by the hon. Minister for Parliamentary Affairs. So, there is no need for Members to get unduly anxious about it. We have time for both these things. We can do it. Let the Question Hour run. That is all. Thank you.

DR. V. MAITREYAN: You move the motion, we will all support it.

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You will not succeed in this. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है ...(व्यवधान)... मैं प्रस्ताव करता हूँ ...(व्यवधान)... मेरा resolution है ...(व्यवधान)... रूल 267 के तहत मेरा resolution है ...(व्यवधान)... हम प्रस्ताव कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान)... हम प्रस्ताव कर सकते हैं। ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: He has not moved the motion. ...(Interruptions)...

He has not moved the motion. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, हम प्रस्ताव मूव कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, let him move the motion, and let the House decide on it. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, you can't move a motion verbally. ...(Interruptions)... I am sorry, you have not moved the motion. आप

प्रस्ताव verbally नहीं दे सकते हैं, आपको प्रोसीज़र मालूम है, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: चेयरमैन सर ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: इसका क्या फायदा है? देखिए अगर आप हाउस disrupt करेंगे, तो हाउस adjourn होगा। इससे क्या फायदा होगा?

DR. V. MAITREYAN: We want the discussion earlier, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, no; you will get your discussion.
...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: चेयरमैन सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।
...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, आप लोग एक मिनट सुनिए। केशव राव जी, कृपया आप बैठ जाइए। कल शाम को आप सबने देखा कि कितना अच्छा डिस्कशन हुआ। आज उसी तरह का डिस्कशन होगा, काफी समय है, आपको कोई चिंता नहीं है। We have discussed it in the morning meeting. Please allow the Question Hour to proceed. That is all. अगर आप इस तरफ, उस तरफ, हर तरफ से disruption करेंगे, तो चेयर के पास कोई चारा नहीं रहेगा, but to adjourn the House.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, यह disruption शब्द निकाल दीजिए, हम लोग disruption नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: तो आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मेरी बात तो सुनिए। बहुत से सदस्यों को एक बजे जाना है, उनके तमाम कार्यक्रम बने हुए हैं, पूरे सदन की इच्छा है कि Constitution Amendment Bill पर बहस शुरू कर दी जाए और एक बजे तक इस पर वोटिंग हो जाए। ...(व्यवधान)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, let me say one thing. ...(Interruptions)...

Please allow me. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please sit down. ...(Interruptions)...

नरेश जी, कृपया आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

One minute, please ... (Interruptions)...

The schedule for the two Houses of Parliament is given by the Government. It is up to 14th of August unless changed again by the Government. यह कैसे किसी मेम्बर ने presume कर लिया कि 14th का मतलब है 12 o'clock on 14th or 4 o'clock on 14th. ... (Interruptions)...

SHRI Y.S. CHOWDARY: Sir, that was the understanding yesterday. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: The House has a practice... No, no; I am sorry. ... (Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-14.08.2014

DR. V. MAITREYAN: Sir, schedule of Independence Day is also for 15th morning, and we have to reach our destination in the night. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I am working on the assumption that all this has been taken into account by the Government when announcing the schedule. We are all aware of it.

(Contd. by 1C-USY)

USY-MCM/1C/11.10

MR. CHAIRMAN (CONTD.): We are all trying to finish it by early afternoon. (Interruptions)... No, you can't make that demand because it is not a valid demand. That's all. (Interruptions)...
वेंकैया जी, बोलिए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, nobody is in a hurry, neither the Government nor the Opposition, to my knowledge. But, yesterday, when this matter came in the absence of the Chairman, when the Deputy Chairman was presiding the House, the Members had expressed their concerns that they have to reach their destinations and be present for the flag hoisting ceremony in their respective constituencies at DC

Uncorrected/ Not for Publication-14.08.2014

Headquarters. That being the case, it was discussed yesterday and a broad consensus was arrived at that if we were able to conclude it by lunch time, it would be easy for the Members to leave for their respective constituencies. Accordingly, if I am right, the Secretariat can correct me, the Deputy Chairman had also announced that voting will take place at 1 o' clock. That was announced....(Interruptions)... We are not arguing with each other. So, you can put to vote what had been announced yesterday and if the House decides that we will be able to complete it by 1 o' clock and have voting and after that hon. Members can leave, I think, it will be good. It is not that the Members want to rush through this or the Members want to avoid discussion in this House. Members very much wanted to discuss it in the House. But the sanctity of August 15 and the logistics involved in reaching out to distances was the background of the discussion, yesterday. That is why I submit to you to take the sense of the House in the matter. There is no question of discussion that this is not the tradition of suspending the Question Hour. Sometimes, as the Chair rightly observed, the House is adjourned because of disruptions. It had happened for ten days. But my request is not to call it as a

'disruption'. If the Chair takes the sense of the House and if everybody agrees to it, then, let us go by that and complete it by 1 o'clock. But if the Chair decides otherwise, the Government has no problem either way. But the understanding reached yesterday was this.(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Venkaiahji, this matter has been discussed, this morning, with your colleague. The point is, there are different views. The Chair is aware that there are different views. There may be more people of one view and less people of one view. For the Chair, it is very difficult to decide. The core matter is कि हमारे पास समय है कि नहीं उन दोनों बिलों को खत्म करने के लिए। जजमेंट यह है और यह चीज डिटेल् में डिस्कस हुई है कि हमारे पास समय है, तो फिर अपनी जो प्रैक्टिस है कल कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सेंस ऑफ हाउस यह है कि आप प्रश्नकाल मत चलाइए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चेयर की पोजिशन एप्रिशिएट कीजिए। The Chair is assuring the Members that there is enough time to go through the procedures. हमारे पास अमेंडमेंट्स अभी आ रहे हैं। जब तक वे अमेंटमेंट्स सर्कुलेट नहीं होंगे तो दूसरा ऑब्जेक्शन उठ जाएगा।

DR. V. MAITREYAN: Sir, there may be enough time. But there should be enough number too at the time of voting.(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: We appreciate the requirement, Maitreyanji. We appreciate the requirement. But the amendments are still coming in. I have just announced कि साढ़े ग्यारह बजे तक अमेंडमेंट्स हम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। तो बगैर अमेंडमेंट्स के आप कैसे उस पर कोई कार्यवाही करेंगे? Amendments have to be circulated. So, please understand the practicality.(Interruptions)... Sharadji, may I request you to please allow the Question Hour to run.(Interruptions)... Q.No. 521.

Q. NO. 521

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, the Kamalnathan Committee and the Sinha Committee have been constituted, based on the urgency and the requirements of both the States, to deal with the important issue of division of officers of both the State level and the All India Services. How much time will this exercise take? The sufferings are too much.(Interruptions)... It is not happening. Will the hon. Minister elaborate on the timeframe and how will it be done?

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has put a very critical question. May I share with this august House that soon after the new Government took over, one of the most challenging jobs before us was the allocation of the cadre and employees between the two States and the urgency was to make the State of Telangana functional by 02nd of June. Accordingly, as per the Andhra Pradesh Reorganization Bill of 2014, two Committees had been constituted.

(Contd. by 1d — PK)

PK-HMS/1D/11.15

DR. JITENDRA SINGH (CONTD.): As has been rightly pointed out by the hon. Member, the Pratyush Sinha Committee was meant for the

Q. No. 521 (contd.)

allocation of the All-India Services, whereas the Kamalanathan Committee was for the State employees. Now, considering the urgency of the Telangana State coming into being and becoming functional from the beginning of June, a provisional allocation was made and, thereafter, the final allocation was taken up. As of today, the status currently is that the Pratyush Sinha Committee Report has already been made available to us and the process of the allocation of the All-India Services employees is already going on, whereas the Kamalanathan Committee held its most recent meeting only yesterday at Hyderabad. The provisional allocation has been made. As you would recall that even in the Reorganisation Bill, a provision was made that the personnel orders will be valid for one year from the appointed day, that is, 2nd June. Thereby, what I am trying to state is that even though we still have about seven, eight months, as per the Ordinance, at our disposal to conclude this exercise but we hope that we would be doing it much earlier than that, considering the preferences and the sentiments of all the sections engaged in this sensitive exercise of allocation between the two States.

Q. No. 521 (contd.)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, second question.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I am happy that the hon. Minister has elaborated on this. But I would like to know from the Minister what is happening to the notice of the Prime Minister who is sitting here. Sir, pending the provisional allocation is fine. Everybody has to do, but as regards pending the outcome of the final allocation, what is happening is, there is unrest because no officer is putting in his best efforts. Thereby, there is a lot of delay in decision making. That is part (a).

MR. CHAIRMAN: No. Put only one question.

SHRI JESUDASU SEELAM: No, no; I am not saying anything. I am asking the question. I have not yet asked. I am telling you the situation. Part (b) is, because of this uncertainty, there are a lot of pronouncements by some leaders from both the sides that the locals will be sent out. Actually, if you take the number, it is not exactly that the people hailing from the two regions will be sufficient for both the regions. There may be give and take. So, in view of the emotional sentiments and provocation made by different leaders from both the

Q. No. 521 (contd.)

States, would the Prime Minister be kind enough to call both the Chief Ministers and have a meeting so that situation is not escalated till the finalization of the report? ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI JESUDASU SEELAM: By when will this finalization take place?

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, I appreciate the sentiments and the sensibilities of the hon. Member. His question is in two parts. (a) As far as the psychological fear is concerned, I think there is absolutely no room for a psychological fear and we would make all efforts to allay if there is any. As far as part (b) is concerned, about the various kinds of announcements that are being made, possibly, speculative too, which are creating some kind of apprehensions among the employees, I wish to share with this august House that the exercise is being done with as much transparency as at our command. Just to cite an example, as far as the Pratyush Sinha Committee Report is concerned, the exercise is already in its final stages; whatever allocation has been done is being put on the website and sufficient time is being given to each of the employees to

Q. No. 521 (contd.)

register his or her grievance. As far as the State cadre is concerned, the Kamalanathan Committee also has made a provision. We have set up a Committee of the Chief Secretaries of both the States, Andhra Pradesh and Telangana, respectively. If there is any grievance, that can be put there. Therefore, I don't think there should be any room for any apprehension or any clandestine exercise being undertaken. The final recommendations will be available very soon, and as far as possible, the consideration of keeping the officers or the employees in their local State are being worked out. If not, then the most rational, objective and impartial procedure will be adopted.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has just explained the procedure and process, but the real story is that no officer is working.

(Contd. by SKC/1E)

SKC-KLG/1E/11.20

SHRI Y.S. CHOWDARY (Contd.): So, I would request the hon. Minister to tell us by which date the cadre allocation will be done. That is my question. What is the date by which it is going to be done?

Q. No. 521 (contd.)

DR. JITENDRA SINGH: Sir, as I stated in the beginning, we were allotted one year for the allocation, but we are going to do it faster than that. The provisional allocation was done on the 31st of May itself, even before the Telangana State came into being. Now, as far as the final allocation is concerned, as I stated earlier, the exercise is almost complete. But, as I said, we want to be more transparent and so, we are giving time to the employees to also register their grievances. But, very soon, maybe in the next few weeks or so, the exercise would be accomplished.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I wish to ask the same question that Mr. Chowdary has asked. Is there any time frame? You have provisionally allotted 42 IAS officers as per the recommendations of the Pratyush Sinha Committee. Half of them are not working, for the simple reason that because of the guidelines that you earlier announced about their options, nativity, etc., they think that they would have to go to the other State. So, there is no finality. You need to take a call on that. Secondly, you must tell us something about the Kamalanathan Committee's recommendations as well, as Mr.

Q. No. 521 (contd.)

Chowdary had asked, because they are on strike. It is not only not working, but the Telangana NGOs have struck work and said that unless Clause 18(f) is revisited, they will not adopt it. So, it is necessary that you be very clear about it. I am not saying that you have to do it immediately, within a month or two, but, let there be some clarity. You should be clear that such and such guideline would remain. Also, that should also be apolitical. As Mr. Seelam has said, there has to be some kind of coordination and harmony between two authorities in order to do it.

Sir, the question I am asking is this. The DoPT's officers' list was signed only after seven days of submission of the Report by the Prime Minister. Then, it has to be put up on the website. Once it is on the website, you would then get the complaints, grievances, etc. Then again, it will go back to a Committee to be decided upon and then come back. This is the explanation being offered by the officers themselves, so much so that the entire administration is coming — I would not say, has come — to a standstill in a few sections, where

Q. No. 521 (contd.)

these officers have been seated. I want to ask the question, since this is the Question Hour, from the Minister...

MR. CHAIRMAN: Please do without the introduction!

DR. K. KESHAVA RAO: Have you factored in these issues, which I have brought to your notice, time and again, both in view of the under the Kamalanathan Committee Report and the Pratyush Sinha Committee Report?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairman, Sir, the hon. Member's concern is well taken. My only complaint is that so many questions were asked together that I am not able to recall which was the first one!

MR. CHAIRMAN: Please answer one! ...(Interruptions)...

DR. JITENDRA SINGH: Anyway, understanding the gist of the matter, the allocation procedure adopted was not arbitrary or subjective, nor was it changed from time to time. The hon. Member was referring to the all India officers. It was strictly...(Interruptions)...

Please let me complete.

Q. No. 521 (contd.)

It is strictly by the guidelines and procedures laid down by the Pratyush Sinha Committee. If you want, I can even spell out the procedure for the benefit of hon. Members. ...(Interruptions)... If you want, I can do that, but that's not required here; we have placed it along with the answer. Secondly, it would also not be right to say that both the States were not involved. For example, in the Pratyush Sinha Committee itself, whereas the Chairman was Pratyush Sinha, the Chief Secretary of Andhra Pradesh and the Chief Secretary of Telangana were both members. In addition, there was a Special Secretary from the Ministry of Home Affairs from New Delhi to look after the IAS cadre interests; there was a member from the Indian Foreign Services also to look after the IFS cadre, and an Additional Secretary from DoPT. So, the Pratyush Sinha Committee itself has sought to be as comprehensive and inclusive as possible, and the guidelines followed are not arbitrarily made by DoPT or by the Government, but only following the Pratyush Sinha Committee guidelines and the procedures laid down by it....(Interruptions)...

Q. No. 521 (contd.)

SHRI JESUDASU SEELAM: There has been no sensitization of the ground...(Interruptions)...

श्री सभापति: नहीं, बैठिए। आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सीलम जी।
...(व्यवधान)...

DR. K. KESHAVA RAO: You must go back to the ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: It should be done by the Government, not the officials. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Seelamji, please. ...(Interruptions)... Mr. Seelam, you can't do this. ...(Interruptions)... No, you can't do this. ...(Interruptions)... You can't do this. ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: People at the official level will not be able to do it. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please do not ...(Interruptions)... Mr. Rapolu.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Sir, the Government has to...(Interruptions)... We all appreciate the procedures and processes, but there is ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You have asked your question.

रापोलू जी, पूछिए अपना सवाल।

(FOLLOWED BY HK/1E)

HK-MP/1F/11.25

Q.No.521 (contd.)

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Chairman, Sir, as the hon. Minister rightly pointed out, right from 30th June, 2013, various Ministries of the Union Government during UPA and afterwards, day in and day out, are concentrating on smoothening the situation in allocation of employees and officials. In between, before the appointed day, there were certain doubts crept in with the decisions of very senior officials belonging to the States. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I am coming to the question. ...(Interruptions)... Complications have created a lot of tensions among the lower level cadres of both the States. I also appreciate the efforts of the residuary State of Andhra Pradesh to shift certain Departments to the capital of the State Vijayawada such as Agriculture, Fisheries and other Departments. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Is there any provision with the Union Government to look after the complications created by the

Q. No. 521 (contd.)

higher officials before the appointed day which are mongering and irritating the minds of employees of both the States?

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, as I stated earlier, nothing has been done subjectively or arbitrarily as far as senior officers are concerned. You go through the guidelines laid down by the Pratyush Sinha Committee; it has already been put on the website. As far as the senior-most officers are concerned, the allocation was made, primarily considering, by name or the preference of the two individual States. The allocation is made by the roster that we followed on the basis of districts -- 13 to Andhra and 10 to Telangana making it 13:10 for the allocation of posts. And then a roster system for the allocation of the IAS officers was followed for the cadre lower than the senior-most cadre. So, we have gone strictly by that. Even in that, we have tried to accommodate, as far as possible, the locals of the two individual States. If they could get accommodated in individual States, they were not necessarily put into that. But whenever that didn't happen, the roster process, considered more objective and impartial, was resorted to and the senior-most officers were, of

Q. No. 521 (contd.)

course, with the compliance of the two States, allocated in the interests of the two States and by the consent and the willingness of the two States of Telangana and Andhra Pradesh.

(Ends)

प्रश्न संख्या 522

श्री बसावाराज पाटिल : माननीय सभापति जी, जैसी कि यहां पर जानकारी दी गई है, इसके लगभग 46 करोड़ listeners हैं। आज मीडिया के नाम पर काफी हो-हल्ला चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो ऑल इंडिया रेडियो के अलग-अलग चैनल्स हैं, आज भी इनकी प्यूरिटी इतनी बनी हुई है कि वे देश के हित में अत्यंत उत्तम हैं। तो इनको बनाए रखने में सरकार और क्या कदम उठाएगी, जिसके कारण इनके listeners की संख्या ज्यादा बढ़े, जिससे देश में बहुत हितकारी वातावरण निर्माण करने में लाभ होगा, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएं।

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आकाशवाणी का होना बहुत अहम है। आकाशवाणी के 413 केंद्र हैं, एफएम के 4 गोल्ड, 23 रेनबो और विविध भारती के 37 चैनल्स हैं। 86 लोकल रेडियो स्टेशन्स हैं, एफएम रिले करने वाले भी 93 स्टेशन्स हैं। जैसा कि एक सर्वे में आया, इनके द्वारा 46 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाता है, लेकिन ये और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचें? आज मोबाइल का भी बहुत प्रसार हुआ है और जितनी जल्दी हम एफएमाइजेशन करेंगे और एफएम का frequency modulation ऐसा है, जिसके आधार पर आज देश में स्मार्ट फोन्स बीस करोड़ से ज्यादा हो गए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अगर मोबाइल पर रेडियो सुनाई देता है, तो यह सबसे ज्यादा प्रसार की बात है। इसलिए एफएमाइजेशन का एक कार्यक्रम

Q. No. 522 (contd.)

बनाया गया है और आने वाले पांच सालों में ज्यादा से ज्यादा केंद्र एफएम पर होंगे और उनके द्वारा उसका बहुत प्रचार-प्रसार होगा।

श्री बसावाराज पाटिल : सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल स्पेशली एफएम रेडियो से संबंधित है। जैसा बाहर प्रचार किया जाता है, लेकिन जब एप्लिकेशन देते हैं, प्रोसीजर के आधार पर भी और फाइल के आधार पर भी, कई बार महीनों तक वह फाइल वहां पड़ी रहती है और उसको कोई नहीं देखता है। एफएम रेडियो लोकल कल्चर को बढ़ाने की दृष्टि से एक पावरफुल चैनल है, तो इसके बारे में मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री सभापति : एक प्रश्न..

श्री बसावाराज पाटिल : एक ही में दो प्रश्न हैं, छोटी बात है, मैं लंबा प्रश्न नहीं पूछूंगा। नंबर एक, एफएम चैनल को पॉपुलर करने की दृष्टि से उसकी जो रेंज है, क्या आप उसे बढ़ाएंगे?

(1G/SC-PB पर जारी)

PB-SC/1G/11.30

श्री बसावाराज पाटिल (क्रमागत) : ऐसा करने से वहां के आस-पास के गांव वालों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप चीपेस्ट रेट में पॉकेट रेडियो

Q. No. 522 (contd.)

जनता को देने की व्यवस्था करेंगे तो उससे जनता को बहुत लाभ होगा। इसके बारे में माननीय मंत्री जी जवाब दें और जो हर्डल्स हैं, उन्हें दूर करें।

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति महोदय, जो सुझाव आए हैं, निश्चित रूप से वे अच्छे सुझाव हैं। जैसा कहते हैं कि these are suggestions for action. मैं एक बात बता देता हूँ कि जो डिले होता था, निर्णय प्रक्रिया में विलम्ब होता था, उसका हमने सरलीकरण किया है और अब जो भी फाइल्स आती हैं, वे रखी नहीं रहेंगी, एक समयबद्ध सीमा में उनका निपटारा होगा और अच्छे दिन आ गए हैं, यह आपको प्रत्ययन होगा।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, while the efforts to spread the message through FM on smart phones and other such devices is very good, the people who actually spread the message are the Radio Jockeys or the RJs. Is the Minister aware -- and if he is, what is the solution to this -- that in some stations across the country those young men and women have been asked to retire after they reach the age of 35? What great biological change takes place that RJs across the country are being asked to retire? Well, the RJs are the people who take the radio messages across to millions of listeners. What is the reason to retire

Q. No. 522 (contd.)

all these young boys and girls at 35 as we have read in the media in the last two weeks?

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा है, let me assure him that as soon as it came to my knowledge that some Radio Jockeys, particularly, in Kolkata are asked to retire voluntarily at 35, we have already held it up, and we have stayed it because हमने देखा है कि माननीय अमीन सयानी जी की इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी आवाज़ कैसी है। आवाज़ सशक्त होनी चाहिए, आवाज़ सही होनी चाहिए, उसका उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मैं सदन को यह एश्योर करना चाहता हूँ कि आरजेज़ को इस तरह से नहीं निकाला जाएगा। ..(व्यवधान)..

श्री सीताराम येचुरी : अमीन सयानी जी 80 साल की उम्र में अभी भी रेडियो जॉकी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर : वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको स्टे दिया है।..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Shrimati Ambika Soni. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... अम्बिका सोनी जी, आप अपना सवाल पूछिए।

Q. No. 522 (contd.)

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, through you, I would like to bring about that this answer given to the question is inadequate and not complete. The question asks about the number of radio stations in the country, not the radio stations of the All India Radio alone. A very important radio component today, a radio station, is the community radio station. I remember, a couple of years ago, we have brought them up to 132. There is no mention of community radio station.

The second thing that I want to ask the Minister is, there was in the pipeline an idea about allowing FM radio stations to broadcast news. Has it come out of the pipeline to become an actuality?

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति महोदय, माननीया सदस्या पहले इस विभाग को नेतृत्व दे रही थीं, उन्हें इस बारे में पता है कि कम्युनिटी रेडियो सचमुच में जनआंदोलन बने, लोगों तक पहुंचने का साधन बने, इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आज उनकी संख्या 243 है, प्राइवेट चैनल्स के साथ मिलाकर। कम्युनिटी रेडियो को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका विस्तार और तीव्र गति से हो, इसके लिए अनुदान की योजना में बदलाव करने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। हमने 700 का एक टारगेट बनाया है ताकि यह जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचे। ..(व्यवधान)..

Q. No. 522 (contd.)

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I asked about the news in the FM radio.

MR. CHAIRMAN: No, no, one question only. Please. Shrimati Jaya Bachchan.

श्रीमती जया बच्चन : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि जो प्राइवेट रेडियोज़ हैं, उनके जॉकीज़, जिनकी आप बात कर रहे थे, वे किस तरह की languages यूज़ करते हैं, किस तरह के जोक्स उसमें आते हैं?

(Contd. by 1h/KSK)

pb/sc -- KSK/GS/11.35/1H

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (CONTD.): They are absolutely objectionable, very bad and the latest thing is that they have started giving news of Parliament and they mimic a lot of Members of Parliament who have spoken. So, are you going to do something about it because this is really not palatable?

SHRI TARUN VIJAY: Sir, I associate myself with the point raised by Shrimati Jaya Bachchan. This trend is becoming atrocious.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, we all associate.

Q. No. 522 (contd.)

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर मसला है। मैंने पहले जो बताया है वह आकाशवाणी, विविध भारती और एफ.एम. जो हमारे अपने सरकारी माध्यमों के रेडियो जॉकीज़ हैं, उनके बारे में बताया है। जहां तक प्राइवेट रेडियो जॉकीज़ की बात है, धीरे-धीरे double meaning की या दूसरी तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए जैसा कि आपने न्यूज़ की बात कही है, अभी तो न्यूज़ अलाउड नहीं है। What we are allowing, and thinking to allow, is about the All-India Radio news clips. That is only what we are thinking right now. But regarding commentary, what she has said is absolutely serious and we have an Electronic Media Monitoring Centre, which is monitoring this. हम ऐसी रिपोर्ट्स को जल्दी देखकर, उस पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में तुरन्त विचार कर रहे हैं क्योंकि यह बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है जो ठीक नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, जया जी ने रेडियो जॉकीज़ पर गंदी लेंग्वेज के इस्तेमाल का प्रश्न उठाया है, क्या आप इसे रोकेंगे? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 523.

(Ends)

Q.No. 523

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I was feeling in my mind that if this issue had come up before this Minister, it would have received a better treatment. But the question was whether this Ministry had received proposals from the Jammu and Kashmir Government. The reply is, 'yes'. But when I received this written statement this morning, I found that for major schemes like STEP, SWADHAR, Financial Assistance for Working Women's Hostel, and UJJAWALA, this Ministry has not received any proposals from the J&K Government during the last three years. Now, the question would arise whether it is the responsibility of the Government of Jammu and Kashmir. It is not so because I have been in various Committees and I have seen as to how these schemes are being monitored. We have a special status. Therefore, in implementation of schemes, we suffer in a special way because there is no monitoring.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, it is a very important question. The question is that they have not received the proposals. But what is the system of monitoring?

Q. No. 523 (contd.)

MR. CHAIRMAN: Thank you.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Kindly listen to me because I have dealt with this issue in the Committee also. There is a Standing Committee on Rural Development. I will not talk about Jammu and Kashmir. Momentarily, I will talk about Andaman and Nicobar Islands.

MR. CHAIRMAN: Please put the question. We are not discussing Andaman and Nicobar.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: For the last five years, there was a Commissioner who could not forward any scheme to the Government of India. Now, I raise a question. These major schemes have not been implemented. Did the Secretary to the Government of India go to J&K to hold a meeting there? I am asking this because the system is that the senior officer here writes a letter and then waits for the reply for two years. This is not only the case of Jammu and Kashmir but also of Andaman and Nicobar.

MR. CHAIRMAN: Prof. Soz, we are not discussing Andaman and Nicobar.

Q. No. 523 (contd.)

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: The hon. Minister should look into it as to why the Government of India did not ensure implementation of these major schemes.

MR. CHAIRMAN: Let the specific questions be answered.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, the Government of India has given a large number of schemes to J&K under different names, like STEP, which is to promote different schemes for NGOs. We have given them SWADHAR, and we have given them financial assistance for working women's hostels. Since 2013, the Government has written letters, especially since I became the Minister, asking if J&K Government would like anything. We have received absolutely no reply in spite of phone calls and letters. For instance, even for these One-Stop Crisis Centres, that we are planning to set up, we have written repeatedly to the Chief Minister and to the Members of Parliament from J&K asking them to reply to us whether they would like to have these Centres. If so, we would be happy to build them.

(Contd. by 1J — GSP)

GSP-ASC-11.40-1J

Q. No. 523 (contd.)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI (CONTD.): Now, I don't know what you mean by monitoring. We are monitoring the schemes that we have given; well, we can't possibly monitor schemes that we have not given. We can just simply write. The laws say that you have to write and ask, and, then, we will be happy to give them to you.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: The system must change. The phone calls are not, you see, that important. Essentially, the Government of India is entrusted to do something for the welfare of people of India. That is not happening. I gave an example of Andaman and Nicobar Islands. Kindly look into that, and, then, you look into Jammu and Kashmir. Sir, so many schemes have been floated but the hon. Minister will see from records that you have dealt mostly with Government organizations. But when you come to credible NGOs, you sanction projects for mushroom cultivation and handicrafts in Jammu. It is very nice. For Kashmir, you sanction projects for slum development programme, and, say that the sector is goatry. But to my information, the progress of this sector is not

Q. No. 523 (contd.)

good. I want to raise a particular question to the Minister. I hope the hon. Minister will apply her mind. As far as sanctioning a project for Jammu for handicrafts is concerned, it is very good, but you must know that handicrafts of Kashmir, such as, carpets, shawls, paper *mache*, wood carving, are world-famous arts and crafts. Kashmir has suffered a great deal during militancy.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, it is said that 70,000 people were killed. It's a small valley. But this sector is neglected by the Ministry. You have very laudable schemes and you can afford to do it. Change the monitoring. The Secretary to the Government of India must travel to the State, at least, once in three months, hold a meeting and get the schemes implemented. Now, what you will do, particularly, for promotion of arts and crafts of Kashmir, can change the things. Please do that.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, the Central Government has not refused any money at all. In fact, we would be delighted to give you as many schemes as possible, especially, in the area of

Q. No. 523 (contd.)

handicrafts because we all are very, very proud of handicrafts of Jammu and Kashmir. It is just that you have to ask for them. I can send the Secretary. In fact, I am happy to do so.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I will request you to visit yourself. ... (Interruptions) ...

श्री सभापति : सोज़ साहब प्लीज़ ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I am happy also to go and see myself. In fact, it would be nice to visit Kashmir but the problem is that even if I go or a Secretary goes, unless you have some scheme that has been worked out, I can't just throw money at it. India needs this money; we can't just throw it away. If you don't have land or you don't have beneficiaries or you don't have a scheme worked out, I can't possibly just dump money and come back. So, I would suggest you to please ask the Government of Jammu and Kashmir to send proposals, and I promise you that they would be dealt with expeditiously.

SHRI ANIL DESAI: Sir, through you, I would like to ask the Minister whether the people of Jammu and Kashmir, especially, women and

Q. No. 523 (contd.)

children will be benefited by the schemes floated by the Government of India. I want to know from the hon. Minister as to whether the families of *Kashmiri Pandits*, their women and children, who were driven out by the militant movement of separatists, will also be the beneficiaries of these schemes. Will they be included in this?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, this Ministry gives a grant to the J&K Rehabilitation Council in the form of a corpus. Of course, the refugees would be included in this, and, I would be really happy to help them as much as I can.

SHRI K.T.S. TULSI: Hon. Chairman, Sir, I understand that this is an open-ended question. It talks about the proposals for taking up the schemes and it is addressed to the Ministry of Women and Child Development. There is a scheme, I believe, or, there is a proposal, which is under active consideration, of conferring powers of search, seizure and arrest with regard to the women who are victims of sexual harassment or domestic violence, etc. Is that proposal going to be applied to Jammu and Kashmir or not? That is my question.

(followed by SK-1K)

SK/1K/11.45

Q. No. 523 (contd.)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Actually, Sir, I haven't understood the question. What particular project is the Member talking about?

SHRI K.T.S. TULSI: This is ..(Interruptions).. National Commission for Women being given the power to arrest, search and seizure. These powers are being conferred on them so that the women who are victims of sexual harassment or domestic violence can easily have access to justice. Is that going to be made available to Jammu & Kashmir or not?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, National Commission for Women does not have these powers as yet. When and if the Government decides that it should have these powers, I am sure it will apply to the whole of India. As you know, Kashmir has special status. So, they then have to sign. They have their own NCW Commission. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Please read part 'b' of the question, "If so, the details regarding organizations recommended by the State

Q. No. 523 (contd.)

Government". So, if there is no recommendation by the State Government, the question does not arise. Now, Shri Ramakrishna. No question? Now, Shri Ratanpuri.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, the hon. Minister has said that ..(Interruptions)..

SHRI AVINASH RAI KHANNA: Sir, he has the next question. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I know, but there is no other question. What can I do? I follow the practice of three questions. That's all.

SHRI G.N. RATANPURI: It is supplementary. ..(Interruptions).. It is supplementary.

The hon. Minister has said that she has written letters to the State Government and also to the Members of Parliament. I am one of the ten Members of Parliament from Jammu & Kashmir. I have not received any letter, any communication, for the last more than five years from your Ministry. Now, as you have said, you intend to send your Secretary. I would suggest you to send a team of officers to Srinagar and convene a meeting where the Members of Parliament

Q. No. 523 (contd.)

from Jammu & Kashmir are also invited and discuss certain schemes for the welfare of women and children belonging to Jammu & Kashmir.

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion.

SHRI G.N. RATANPURI: And, will you kindly provide me the copies of communications that have been sent during the last five-six years to the Members of Parliament because I have not received even one?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Actually, I should clarify that I have sent a letter to every single Member of the Lok Sabha asking them about this. A lot of them have replied to me and said, 'yes, we will give you the land and thank you for asking us'. We have not given it to the Rajya Sabha because it is district-specific, constituency-specific. That's why. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Thank you. ..(Interruptions)..

SHRI P. RAJEEVE: That is the question of dignity of this House. ..(Interruptions)..

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I will be happy ..(Interruptions)..

Q. No. 523 (contd.)

MR. CHAIRMAN: It is a procedural matter. It can be sorted out.
..(Interruptions)..

SHRI D.P. TRIPATHI: Sir, what is she saying? ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: All right. Fair enough. ..(Interruptions)..

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I will be happy to
..(Interruptions).. If you believe ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: It is a procedural matter. It can be sorted out.
Thank you.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, I am happy to write to
the Rajya Sabha as well and I will do so tomorrow. (Ends)

Q. No. 524

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, it is a more than 13-year old data in reply to my question. According to the data available with me, in Jammu & Kashmir, we have more than 2,00,000 orphans, more than 50,000 widows, more than 8,000 half widows, thousands of destitute, old people, who don't have any resources, any means of livelihood and many thousand handicapped, who got handicapped in grenade explosions, in explosions of unexploded arsenal in firing ranges and if the process continues ...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI G.N. RATANPURI: I have been told that 19 crore rupees of corpus has been provided by the Government of India to the State Rehabilitation Council. Out of which, last year, just about two crore rupees have been distributed among 3,598 widows; 2,210 old age people; 1,806 orphans and 1,087 handicapped people. Giving the enormity of the situation, I can safely presume that Government has chosen ignorance or the question reflects lack of seriousness.

(Followed by YSR/1L)

-SK/YSR-LP/11.50/1L

Q.No.524 (contd.)

MR. CHAIRMAN: That is not a question. That is a view. Please ask a question.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, I will repeat my question. Does the Government intend to conduct a survey of orphans, widows, handicapped people and the destitute in Jammu and Kashmir and come up with specific schemes?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, firstly, I would like to inform the hon. Member that the money for the Rehabilitation Council is given by the Ministry of Home Affairs. It is Rs.19 crore. You have to use the interest of this which the Government of Jammu and Kashmir has done. They have used Rs.2 crore. It is obviously the interest of this corpus.

Secondly, you asked about the schemes. ...(Interruptions)... Regarding the Census of widows, the Census has been done. But this Census, I am afraid, is of 2001. I agree with the hon. Member that a census should be done. Since it does not come under my Ministry, I will try and talk to the Ministry involved to see if they could do a census

Q. No. 524 (contd.)

of this. ...(Interruptions).... May I ask whether it is not possible for the Government of Jammu and Kashmir to do a census themselves?

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Second supplementary.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, I think the Government is not serious or, I will repeat, the Government has chosen to be ignorant.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary question?

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, my specific question is this. I will repeat my first question first. My specific question is whether her Ministry intends to have a survey, not the census. Census is a separate issue. She has told me that the results of the Census 2011 are not out on marital status of women. So, she cannot tell the number of widows according to the latest Census. Why cannot the Ministry have a separate specific survey? And why cannot they come up with specific schemes? This is my first question. I will repeat it again.

MR. CHAIRMAN: Thank you. That is enough.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: We do not conduct any census in this Ministry. ...(Interruptions)... Wait a minute.

Q. No. 524 (contd.)

...(Interruptions)... It is a State subject. I can send a team and we can have an overview of the plight of the women there especially that of widows and orphaned children. That is the best that I can do. I can also provide help provided the Government of Jammu and Kashmir sends me proposals for schemes. I am happy to help with special homes for women in distress and for orphaned children short-stay houses. But I cannot do a survey ...(Interruptions)... I cannot do a proper census because it does not come under my Ministry. ...(Interruptions)... It comes under the State. ...(Interruptions)...

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, my second question is this. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, you have asked enough questions. ...(Interruptions)... No, you have asked enough questions. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... Shri Khanna. ...(Interruptions)...

श्री अविनाश राय खन्ना : मैं आपकी बात ..(व्यवधान)..

Q. No. 524 (contd.)

श्री सभापति : प्लीज़ आप बैठ जाइए..(व्यवधान).. You cannot make speeches here. ...(Interruptions)... I am sorry. ...(Interruptions)... Ask specific questions. Don't make speeches.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, my second question is this. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: What is your second question? ...(Interruptions)...

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, my second question is this. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You have asked your second question. ...(Interruptions)... Mr. Khanna. ...(Interruptions)... प्लीज़ आप बैठ जाइए..(व्यवधान).. You have asked two questions. ...(Interruptions)...

श्री अविनाश राय खन्ना : सभापति जी, मेरा बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: You have asked two questions. ...(Interruptions)...

श्री अविनाश राय खन्ना : सभापति जी, दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं..(व्यवधान)..

Q. No. 524 (contd.)

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र से पैसा लेने के लिए प्रपोज़ल नहीं भेजा, दो क्वेश्चन लगातार ऐसे आए हैं। अगर क्वेश्चन का रिप्लाई पढ़ें, तो 2011-12 में 1826 लोगों को, 2012-13 में 1921 लोगों को और 2013-14 में 1806 लोगों को बेनिफिट हुआ, लेकिन अगला प्रपोज़ल नहीं आया।

(1m/akg पर जारी)

AKG-VKK/1M/11.55

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत) : इसका मतलब ...

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

श्री अविनाश राय खन्ना : इसका मतलब जम्मू-कश्मीर सरकार ने, सर यह मेरा सवाल है ...

श्री सभापति : नहीं, नहीं। आप सवाल पूछिए।

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रपोज़ल न भेज कर इतने लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया है। क्या केन्द्रीय सरकार उस सरकार के खिलाफ और उन ऑफिसर्स के खिलाफ, जो प्रपोज़ल न भेजने के लिए रिस्पॉंसिबल हैं, कोई एक्शन लेगी? ...(व्यवधान)...

Q. No. 524 (contd.)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, all I can do is what I promised to Prof. Soz that we will send somebody to Jammu and Kashmir to see if we can get them to increase the number of proposals from zero to whatever they want. I would also like to tell the hon. Member, Mr. Ratanpuri, that a census, as he said, was done in 2011. It is with the Registrar General of India, which belongs to the Ministry of Home Affairs. As soon as it comes in, we will see how we can help them. Regarding taking action against officials, unfortunately, the system does not allow me to do anything more than constantly asking them to send proposals. I would be happy if they send us more proposals.

SHRI D. RAJA: Sir, Jammu and Kashmir has the largest number of widows. There are two categories of widows – one category is of those widows who lost their husbands in different conflicts in the State of Jammu and Kashmir, and the other category is of those widows who do not know whether their husbands are alive or dead because their husbands are declared to have disappeared. In such a situation,

Q. No. 524 (contd.)

has the Union Government any special programme targeting these widows, helping them in rehabilitation and dignified settlement in life?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Sir, we have different schemes. We have short stay homes or other homes for widows or women in distress. This could apply to those kinds of widows. We are happy to give those; however, many are needed. It applies to 50 women at a time. We have schemes for orphaned children. Again, you have to apply for them. We have the STEP scheme to teach them any form of employment-generating talents, vocational talents and again, we are happy to send those to them. I have about eight or nine schemes which would be useful to the widows, but again, they have to be applied for.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : सभापति जी, माननीया मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में यह जानकारी दी है कि देश में अनार्यों की संख्या से सम्बन्धित डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। महोदय, अनाथ बच्चे और विधवा महिलाएँ, जिनको प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार की सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हीं का डेटा केन्द्रीय स्तर पर न रखने की व्यवस्था की जानकारी माननीया मंत्री महोदया ने दी है, जो कि एक बहुत गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से

Q. No. 524 (contd.)

माननीया मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार या आपका विभाग जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत के तमाम प्रदेशों की विधवाओं और अनाथ बच्चों का डेटा केन्द्रीय स्तर पर रखने का कोई प्रोग्राम बनाएगा?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: This is a valuable suggestion. Unfortunately, it has never been included in a census. I am sure we can look into this to see whether we can put it in the next Census.

(Ends)

...(Interruptions)...

प्रश्न संख्या 525

श्री अनिल माधव दवे : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि देश के शहरों के विकास के लिए जो उनका नक्शा बनता है, जो उनकी प्लानिंग होती है, उसके अन्दर बगीचों और खेल के मैदानों की जो स्थिति है ...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

(Ends)